

पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं को ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 1995 रकबा 0.93 हैक्टर अपीलान्ट के पिता श्योकरण उर्फ रामकरण को आवंटित हुई है एवं तत्पश्चात् अपीलान्ट के पूर्वज रामकरण उक्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। रामकरण की मृत्यु दिनांक 26.07.1962 को हो चुकी है एवं उसके वारिसान अपीलान्ट एवं अन्य विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेजी एवं नौखिक साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकमात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए रामकरण पुत्र धन्ना को पृथक व्यक्ति होना वर्णित करते हुए आक्षेपीय आदेश से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर त्रुटि कारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बजरंग लाल पुत्र रामकरण द्वारा श्योकरण व रामकरण के पृथक-पृथक व्यक्ति होने बाबत् साक्ष्य प्रस्तुत की गई है किन्तु उक्त कथनों के समर्थन में किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। वास्तव में श्योकरण उर्फ रामकरण एक ही व्यक्ति है जिसके विधिक वारिस अपीलान्ट एवं अन्य अप्रार्थीगण हैं जिनका हिस्सा विवादित भूमि में नीहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतान नामान्तरकरण से महरूम किये जाने की नीयत से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष बजरंग पुत्र रामकरण द्वारा दिये गये बयान बाबत् किसी प्रकार की जिरह इत्यादि का अवसर अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। पत्रावली में पेशी दिनांक 13.01.2013 नियत की गई जिसमें पत्रावली गांवों के संग अभियान के बाद पेश होने का अंकन किया हुआ है एवं इसके पश्चात् पत्रावली में बिना किसी प्रकार की दिनांक अंकित किए आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का दायित्व है कि रेकार्डेड खातेदार कृषक की मृत्यु पश्चात् मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर मृतक के वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करते। पिछले 40 वर्षों से मृत व्यक्ति के नाम कृषि भूमि चली आ रही है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार कर विवादित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 7 के पक्ष में स्वीकृत किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत जांच कर मौके पर उपस्थित मौतबिरान की उपस्थिति में मौका पर्चा तैयार किया गया है। मौका रिपोर्ट अनुसार रामकरण व श्योकरण अलग-अलग व्यक्ति है। रामकरण उर्फ श्योकरण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। पैरोकार



६४
अदालत अजमेर
२०१३

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017


सरकार ने आगे कथन किया कि अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये गये है एक में रामकरण उर्फ श्योकरण नाम दर्ज है जबकि मृतक श्री भूरा के मृत्यु प्रमाण पत्र में पिता का नाम केवल श्योकरण ही दर्ज है, उसमें उर्फ रामकरण अंकित नहीं है। उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत कर आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त समक्ष न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्त निरस्त की जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है अपीलान्त के दादा का नाम राजस्व रेकार्ड में रामकरण वल्द धन्ना जाट सा0 गुलगांव दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 14.09.2012 के अनुसार रामकरण व श्योकरण श्री धन्ना के अलग-अलग पुत्र है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मृतक श्री भूरा के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पिता का नाम रामकरण दर्ज है। अपीलान्त द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि उनके दादा का नाम रामकरण उर्फ श्योकरण ही है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्त पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर
अजमेर